

# जीवन होगा आसान: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर सरकार का जोर

## क से ज तक, एआइ क्रांति की तैयारी

शादाब अहमद

patrika.com

नई दिल्ली. दुनिया के हर क्षेत्र में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। भारत सरकार ने भी 'क' से लेकर 'ज' तक जीवन के हर क्षेत्र में एआइ क्रांति लाने की तैयारी कर ली है। औद्योगिक क्षेत्र में इसका व्यापक उपयोग बढ़ा है। आम आदमी के जीवन को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इंडिया एआइ मिशन शुरू किया है। आम जनजीवन से जुड़ी स्वास्थ्य, शिक्षा, बैंकिंग, बीमा, खेती, न्यायालय, रेलवे जैसी सेवाओं में एआइ को अपनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने 10 हजार 371 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं, जिसमें इस साल 551 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य है।

एआइ को अपनाने में भारत की तेजी दिखने लगी है। स्टैनफोर्ड एआइ इंडेक्स रिपोर्ट 2024 में भारत का एआइ कौशल प्रसार और गिटहब एआइ परियोजना में पहला स्थान है। ऑक्सफोर्ड एआइ रेडिनेस इंडेक्स में भारत 40 वें स्थान पर है। नैसकॉम एआइ एडॉप्शन इंडेक्स में भारत को 4 में से 2.5 अंक मिले हैं। यह स्कोर भारत में एआइ के महत्वपूर्ण संभावित मूल्य को दर्शाता है। अनुमान है कि भारत वित्त वर्ष 2025-26 तक 500 अरब डॉलर के अवसर को छू सकता है।

एआइ से जहां बड़ी संख्या में नौकरियों पर खतरा बताया जा रहा है, वहीं यह मशीन लर्निंग विशेषज्ञ और सूचना सुरक्षा विश्लेषक बनने के अवसर भी लेकर लाया है। इसके लिए सरकार भी युवाओं को ट्रेनिंग दे रही है।

कृषि, रेलवे, कोर्ट, जीएसटी, शिक्षा, हेल्थ जैसे क्षेत्रों में दिखेगा असर

10,371 करोड़ रुपए का मिशन, इस साल खर्च होंगे 551 करोड़

### शिक्षा: बदल रहा तरीका

एआइ सभी उम्र के लोगों के सीखने के तरीके को बदल रहा है। यह भाषाई बाधाओं को खत्म कर रहा है। सरकार ने भाषिणी परियोजना 2022 में शुरू की, जिसमें 495.51 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया था। इसका उद्देश्य 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं के लिए एआइ संचालित अनुवाद तकनीक विकसित करना है। इसके लिए राष्ट्रीय सार्वजनिक डिजिटल प्लेटफॉर्म विकसित किया जा चुका है। किताबों को डिजिटल बनाने व साहित्यिक चोरी रोकने में भी इसका इस्तेमाल हो रहा है।

### कंप्यूटिंग: एरावत से महारत

एमआईआईटीवाई ने सीडेक के साथ मिलकर एआइ अनुसंधान, विश्लेषण और ज्ञान प्रसार प्लेटफॉर्म (एरावत) विकसित किया है। इस प्लेटफॉर्म की कंप्यूटिंग क्षमता 200 एआई पेटाफ्लॉप्स तक है। इसका उपयोग अनुसंधान प्रयोगशालाओं, वैज्ञानिक समुदाय और स्टार्ट अप कर सकते हैं।

### कृषि: ई-मित्र बॉट लॉन्च

एआइ की मदद से पैदावार बढ़ाने से लेकर मौसम का पूर्वानुमान तक लगाया जा सकता है। दूध उत्पादन में पशुओं की निगरानी में मदद कर रहा है। कृषि मंत्रालय ने 11 भारतीय भाषाओं में पीएम किसान के बारे में एआइ सक्षम किसान ई-मित्र बॉट लॉन्च किया है, ताकि जानकारी आसानी से उपलब्ध हो सके।

### एआइ का प्रयोग

### बढ़ाने की कवायद



### बैंकिंग व बीमा: ऑडिट में आसानी

एआइ की मदद से वित्त, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय की ओर से बैंक, बीमाकर्ता और वित्तीय संस्थानों में धोखाधड़ी का पता लगाने, ऑडिट करने और ऋण के लिए ग्राहकों का मूल्यांकन करने जैसे कई काम शुरू कर दिए गए हैं।

### सुप्रीम कोर्ट: विधिक अनुवाद

कानून व न्याय मंत्रालय एआइ सक्षम एसयूवीएएस (सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा है। यह क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णयों को अनुवाद में सहायता करता है।

### संसद: सटीक लेखन में मदद

संसद भी एआइ क्रांति के तालमेल बिठा रही है। डिजिटल संसद ऐप पर एआइ विधायी प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और पारदर्शिता बढ़ाने में सहायक साबित हो रहा है। इसके माध्यम से संसदीय कार्यवाही के सटीक लेखन में मदद मिल रही है।

### रेलवे: सेवाएं हो रहीं बेहतर

यात्रियों के लिए रेलवे की सेवाओं को बेहतर व सुरक्षित बनाने के लिए एआइ का उपयोग हो रहा है। रेलवे चालकों पर निगरानी के लिए एआइ का उपयोग भी शुरू होने जा रहा है। सिग्नलिंग, ओवरहेड उपकरण, केरिज और वैगन, सामग्री प्रबंधन और सुरक्षा से जुड़े मामलों में एआइ की मदद ली जा रही है।

### स्वास्थ्य: जांच में आई तेजी

बड़ी डेटा विश्लेषण क्षमताओं के चलते एआइ का स्वास्थ्य सेवा में उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एआइ बीमारियों को अधिक तेजी से सटीक पता लगाने, दवा की खोज को गति देने में मदद कर रहा है।

### फ्यूचर स्किल्स प्राइम कार्यक्रम

इसमें एआइ से जुड़े 119 पाठ्यक्रम शामिल हैं। अब तक 1.27 लाख से अधिक युवा प्रशिक्षित हो चुके हैं। 1236 सरकारी अधिकारियों व 292 प्रशिक्षकों को एआइ में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

### युवाओं के लिए भरपूर अवसर

### विश्वेश्वरैया पीएचडी

इसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिकी प्रणाली डिजाइन और आइटी क्षेत्र में एआइ और उभरती तकनीक में पीएचडी बढ़ाना है। पहले चरण में 466 करोड़ दूसरे चरण में 481.93 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं।

### जिम्मेदार एआइ 2022

इस कार्यक्रम का लाभ 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 52 हजार छात्रों को मिल चुका है। वहीं 2552 स्कूलों के 2536 शिक्षकों को एआइ के बुनियादी ज्ञान की जानकारी दी गई है।

### विकास के लिए एआइ

नेशनल ई-गवर्नेंस डिवीजन व एमआईआईटीवाई ने एआइ कार्यक्रम शुरू किया। इसके तहत कक्षा 8 से 12 तक के स्कूली छात्रों को एआइ तकनीक और सामाजिक कौशल प्रदान किया जाना है।